VNK-VKK/2O/3.00

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : कभी-कभी यह होता है, चुनाव में यह हो रहा था कि हम सिर्फ मार्कशीट के आधार पर नौकरी दे देंगे। ऐसा न हो कि मार्कशीट के आधार पर योग्य लोगों को नौकरी न मिले। जो पढ़ कर पास कर रहा है, उसके लिए 70 परसेंट..... हम लोग जब पढ़ते थे, तब अगर फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी, तो ऐसा समझते थे कि आकाश से तारे तोड़ लाए हैं। उस समय 4 या 5 बच्चे ही फर्स्ट डिवीजन में पास होते थे। जो लड़का फर्स्ट डिवीजन पास होता था, उसके बारे में ऐसा समझा जाता था कि वह बहुत brilliant लड़का है। अब तो 80 परसेंट बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम AICTE पर नकेल क्यों कर रहे हैं? AICTE ने एजुकेशन कमाई का जरिया क्यों बना रखा है? हमने कभी इस पर विचार किया, इस पर सोचा? क्या पार्लियामेंट सिर्फ इसलिए है कि हमने अपनी बात कह दी, आपने लिख लिया और औपचारिकता पूरी हो गई? अगर वास्तविक रूप से जमीन पर चीजें नहीं उतरीं, तो हम देश का भला नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए यहां नहीं बैठे हैं। हम यहां पर निर्णय लेने के लिए बैठे हुए है। जनता ने हमें इसलिए यहां बैठाया है, क्योंकि यह पॉपुलर गवर्नमेंट है और पॉपुलर गवर्नमेंट में हमारे हित में तमाम निर्णय होंगे, लेकिन निर्णय नहीं हो रहे हैं। अगर निर्णय होते, तो हमें यह कहने की क्या आवश्यकता पड़ती?

आज गर्ल्स एजुकेशन कितनी है? हमारे देश में आज तक वास्तविक रूप से 55 परसेंट भी गर्ल्स एजुकेशन नहीं है, लड़कों की जरूर 70-75 परसेंट तक पहुंच गई है। अगर ऐसा ही रहा और लड़कियों को एजुकेट नहीं किया गया, तो आप कन्या भ्रूण हत्या कैसे रोकेंगे? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? आप लड़कियों की एजुकेशन

को compulsory क्यों नहीं कर देते हैं? अगर लड़कियों की एजुकेशन compulsory हो जाएगी, तो परिवार नियोजन अपने आप लागू हो जाएगा, लेकिन हमने एजुकेशन नहीं दी। हम एजुकेशन की ओर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। हमको इस पर विचार करना चाहिए और इस पर कोई कठोर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप भी कठोर निर्णय न ले सकें, तो फिर मिलीजुली सरकारों से आप कैसे कठोर निर्णय की आशा करेंगे? मैं चाहूंगा कि आप कोई कठोर निर्णय लें और विश्वविद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। जेएनयू में सब कूद पड़े। अब तो हम रोज पढ़ते हैं कि जेएनयू में आज यह हो गया, कल यह हो गया, एबीवीपी ने यह किया, एनएसयूआई ने यह किया, कम्युनिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन ने यह किया। छोड़िए, हम एजुकेशन के सेंटर्स को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं, बल्कि एजुकेशन के सेंटर्स को एजुकेशन का अखाड़ा रहने दें। वहां पर शिक्षा पर चर्चा होनी चाहिए कि कैसे अच्छी शिक्षा हो। हम कैसे देश का भला करें, अगर इस पर चर्चा होगी, तो बहुत अच्छा होगा। राजनीति करने के लिए तो अभी हम, आप, बहुत लोग हैं। अब तो यह है कि सभी लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट हो गया। अब तो जो आईएएस रिटायर होता है, जो अधिकारी रिटायर होता है, वह 60 साल फाइलों का मास्टर होता है और रिटायर होते ही वह कोई दल ज्वॉइन कर लेता है और हम, आप इतनी जल्दी उसको टिकट देते हैं, जैसे उसने कितना बड़ा sacrifice किया है। देश के पूर्व गृह सचिव फौरन मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। अब मैं बहुत चीजें नहीं कहूंगा, हमारे मित्र हैं, भाई हैं, लेकिन राजनीति का भी कोई न कोई एक विद्यालय बना देना चाहिए कि जब तक वहां की डिग्री नहीं लाओगे, तब तक राजनीति में नहीं आ सकते हो। यह राजनीति हर एक के लिए नहीं है।...(व्यवधान)... आज जिसे देखो, खाली

हुआ, उससे पूछो कि क्या कर रहे हो, पहले जैसे था कि हम लैण्ड का काम कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि सब कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यह राजनीति करते-करते, वह राजनीति कम कर रहा होता है, दलाली ज्यादा कर रहा होता है। अब तो कहीं-कहीं ऐसा हो गया कि हर दूसरे घर पर दो लड़के राजनीति में आ गए और राजनीति का मतलब ठेकेदारी, पट्टेदारी। यही तो है, 50 लोग चले गए और डीएम मुर्दाबाद के नारे लगा दिये, डीएम ने कहा... चूंकि डीएम खुद ही इतना कमजोर है, क्योंकि उसकी कलम से इतने गलत काम होते हैं। अगर राजनीति की परिभाषा यह बना दी गई, तो हमको गाली लगती है, क्योंकि जब हम ट्रेनों में चलते हैं, तो कहा जाता है कि नेता जी जा रहे हैं। 'नेता' शब्द गाली हो गया। अगर हम यह नहीं बताएं कि हम एमपी हैं और सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में बैठ जाएं.... मैं इसी से संबंधित एक किस्सा सुना देता हूँ। जितेन्द्र प्रसाद, हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, एक बार हम दोनों लखनऊ मेल से लखनऊ जा रहे थे और मुरादाबाद के पास ट्रेन डिरेल हो गई, तो हम लोगों को उतरना पड़ा। नई ट्रेन आई, उससे हम सब लोग ले जाए जाने लगे, तो हम लोगों को मुरादाबाद से गजरौला तक पहुंचने तक में कितनी गालियां सुननी पड़ीं। हमने उनसे कहा कि भाई साहब, आप यह न बता देना कि आप एमपी हो या हम एमएलए हैं, इसको चुपचाप सुन लो। एक जमाने में 'नेता' शब्द आदर का शब्द था कि नेता जी आ रहे हैं।

(2पी/एनकेआर-बीएचएस पर जारी)

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : आज अगर 'नेता' शब्द गाली का शब्द हो गया है, तो हमें इसकी परिभाषा बदलनी पड़ेगी, अपना आचरण बदलना पड़ेगा। यह नहीं होना चाहिए कि कल तक रिक्शे का किराया नहीं दे पाते थे, आज MLA बन गए तो गाड़ी भी आ गई, पक्का मकान भी बन गया और सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गईं। अगर हमारा स्वरूप ऐसा रहेगा तो नेता के प्रति लोगों के मन में विचार दूसरा होगा। हमें खुद अपना आचरण ठीक करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अगर हम सब लोगों ने ऐसा नहीं किया तो धीरे-धीरे हमारा स्तर गिरता चला जाएगा और गिरता स्तर इस देश के प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा पर आप विचार कर लें। मेरा ख्याल है कि मेरा बोलना सबको ठीक लग रहा होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : आज लग ही नहीं रहा है कि कौन बोल रहा है।

श्री नरेश अग्रवाल : मैं हरदम ऐसे ही बोलता हूं। जब मैं आपका भी स्टेटमेंट सुनता हूं तो अच्छा लगता है कि कम से कम बिहार में अभी भी कोई जयप्रकाश नारायण बाकी है, जो सही चीजों को बोल तो रहा है। अन्यथा आज राजनैतिक दलों में स्तर इतना गिरा हुआ दिखाई देता है कि प्रवचन सुनने को मिलते ही नहीं। लोगों को प्रवचन बोलने में दिक्कत आने लगी है।

अब मैं बैंकों पर आता हूं। इंदिरा जी ने 1971 में बैंकों का nationalization किया था।..(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति : अभी 4 मिनट बाकी हैं।

श्री नरेश अग्रवाल : अगर House allow कर दे, तो मुझे थोड़ा-सा बोलने दीजिए।

श्री उपसभापति : बोलिए, बोलिए।

श्री नरेश अग्रवाल : बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था, क्योंकि तब पूंजीपतियों के Banks थे और गरीबों को सुविधा नहीं थी। राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था कि गरीबी हटाएंगे, बैंक ऋण देंगे, सस्ते ब्याज पर लोगों को ऋण उपलब्ध होगा, उद्योग-धंधे बढ़ेंगे, कुटीर उद्योग बढ़ेगा, देश में बेरोज़गारी दूर होगी लेकिन आज बैंकों का NPA 12 per cent हो गया है। विश्व के किसी भी देश में बैंकों का NPA 12 per cent नहीं होगा। हम 20,000 करोड़ रुपए अपने बजट से देते हैं। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि शायद सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि अब हम अपनी तरफ से बैंकों को कुछ नहीं देंगे। विश्व में ब्याज का LIBOR rate एक से दो per cent से कहीं ऊपर नहीं है लेकिन हमारा कोई बैंक 14 per cent से कम ब्याज पर लोन नहीं देता है। आप किसानों के लिए एक-दो per cent पर लाएं, उसे क्यों नहीं आप LIBOR rate पर देते हैं? आप जितना भी कर्ज विश्व बैंक से ले रहे हैं, यूरोपियन बैंक से ले रहे हैं, जापानी बैंक से ले रहे हैं, सारे बैंकों से आपको लोन एक या दो per cent ब्याज दर पर मिल रहा है, बल्कि एक per cent के आस-पास है, शायद 1.5 per cent है, लेकिन हम ले क्या रहे हैं? धीरे-धीरे जो Savings Bank खाते हैं, उनमें भी हम ब्याज दर कम करते जा रहे हैं। Old age लोगों का क्या हुआ, जो FD कराते थे और सोचते थे कि हमें 8-9 per cent ब्याज मिलेगा। उनकी ब्याज दर आज घटते-घटते 7 per cent तक आ गई। Savings Bank खातों में बैंक कहता है कि अब 3 निकासी से अधिक पर पैसा काटेंगे। उस दिन हमारे मित्र, सीताराम येचुरी जी कह रहे थे कि उन्होंने कोई निकासी भी नहीं की, फिर भी उनके 144 रुपए कट गए। एक नया ATM आ गया, अब तो App भी आ गया। क्या इस

देश में ऐसी व्यवस्था लागू होगी कि हमें पैसा जमा करने पर भी ब्याज देना पड़ेगा? यदि ऐसा हुआ तो यह गरीब देश कैसे चलेगा? ठीक है कि आप Current Account वालों से लीजिए, उनसे कटौती कीजिए, Current Account में हम मना नहीं करते हैं, लेकिन Savings Bank and Fixed Deposits को तो इससे बचाइए। हर बैंक ने अपना Secret Act बना रखा है। Bank Secrecy Act कहता है कि बैंक के कौन बकायेदार हैं, इसे हम open नहीं करेंगे। Finance Committee में मैंने बहुत बार इसका विरोध किया कि गांव के एक गरीब पर अगर 10,000 रुपए भी कर्ज है तो आप तहसील के gate पर लाल अक्षरों से लिख देंगे, लेकिन अगर पूंजीपतियों पर लाखों करोड़ रुपए बकाया है तो आप क्यों उनकी list प्रकाशित नहीं करना चाहते? आज आप declare कर दीजिए कि इस एक्ट को हम समाप्त करते हैं, कल देश के सारे अखबारों में अगर 100 बड़े बकायादारों के नाम आ जाएं तो देश के सामने एक नई क्रांति पैदा हो जाएगी, देश जान जाएगा कि किसके पास देश का कितना रुपया बकाया है और बैंकों में किसने कितना रुपया दिया। नोटबंदी में कितने बड़े लोगों का रुपया बदला गया, किन-किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, आखिर कुछ तो पता लगे, कहीं तो जानकारी मिले। आप Students और किसानों के लिए 2 per cent या 3 per cent ब्याज पर ऋण देने की घोषणा कर दीजिए, क्योंकि बेरोजगारी है, लड़का पढ़कर निकलता है, मां-बाप अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं लेकिन ब्याज नहीं दे पा रहे हैं। क्या हालत देश के सामने है?

(2Q/DS द्वारा जारी)

DS-DC/3.10/2Q

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : वे ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, देश के सामने यह कैसी हालत है? अगर ऐसा किया जाए, तो मैं समझूँगा कि यह देश के साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। आप कुछ स्टेप्स लीजिए। वित्त मंत्री जी यहाँ होते, तो मैं उनसे बहुत-सी चीज़ें कहता। मैं उनसे कहता कि वित्त मंत्री जी, ये-ये सुधार कीजिए। बैंकों के सीएमडीज़ को यह इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए कि अगर कोई एमपी फोन करेगा, तो उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि वह उस एमपी को रिप्लाई दे। मुझे इतने साल यहाँ हो गए, यहाँ मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं और उधर दूसरे साथी भी बैठे हैं। आप किसी भी बैंक के सीएमडी को फोन कर लीजिए, वह कभी लाइन पर नहीं आएगा और वह कभी लौटकर आपसे बात भी नहीं करेगा। आखिर ऐसा क्यों है? हमारा प्रोटोकॉल है और अगर हम बैंक से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, हमारे यहाँ कोई बेरोजगार आया और हम उस बेरोजगार के संबंध में बात करना चाहते हैं, तो बैंक का सीएमडी हमसे बात नहीं करेगा! यह कौन-सी बात हुई? संतोष गंगवार जी, आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए। आप ज्यादा मृदुभाषी हैं, ज्यादा सीधे हैं। राजनीति में सीधा होना बहुत अच्छा नहीं होता है, राजनीति में थोड़ा-सा टेढ़ा भी होना चाहिए। ...(व्यवधान)... मैं इसी मारे कह रहा हूँ, शरीफ तो हम भी बहुत हैं, लेकिन हमारा सर्टिफिकेट दूसरी यूनिवर्सिटी से है, इनका सर्टिफिकेट -- हर साल बैंक से करीब 6-7 हजार करोड़ रुपये माफ होते हैं, यह माफी क्यों हो रही है? माल्या भाग गए, ललित मोदी भी भाग गए, तमाम और लोग जिन्होंने कर्जे लिए, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : उनको हमारी सरकार ने नहीं भगाया है। हम उन सबसे वसूली की कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत मजबूत कार्रवाई

कर रहे हैं। अभी कल या परसों भी एक सवाल पूछा गया था, तो उसके उत्तर में बताया गया है कि ऐसा किया जा रहा है। इसके तथ्य हम आपको बाद में बता देंगे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : इसलिए आप इन पर आरोप मत लगाइए, दु:ख होता है। ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम भी मंत्री थे, तब कह देते थे कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। यह आश्वासन भी नहीं बनता है और कार्यवाही का अंग भी नहीं बनता है। इन शब्दों को राजनीति की डिक्शनरी से निकाल दीजिए। आज आप यह घोषणा कर दीजिए कि जितने बड़े बकायेदार हैं, वे तीन महीने के अंदर या तो ओटीएस कराएँ या बैंकों का रुपया जमा करें। वह रुपया बैंक में जमा होना चाहिए। ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति : ठीक है,नरेश जी।

श्री नरेश अग्रवाल : सर, अभी तो बहुत समय है। हमने सोचा था कि मुझे एक घंटे तक बोलने का मौका मिलेगा।

श्री उपसभापति : आपको बोलते हुए 45 मिनट्स से ज्यादा हो गए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : श्रीमन्, अब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर आते हैं।

श्री उपसभापति : ठीक है, आप पाँच मिनट और ले लीजिए।

श्री गिरिराज सिंह : अभी तो बजट पर बोलना है। ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : मैं तो बजट पर ही बोल रहा हूँ। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके जमाने में क्रूड ऑयल का रेट नहीं बढ़ा। कितनी सेविंग हुई! ...(व्यवधान)... मैंने

वही कहा कि एक जमाने में 120 रुपये तक पहुँच गया था, आज 50-51 रुपये में ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल : 120 डॉलर।

श्री नरेश अग्रवाल : वह 120 डॉलर प्रति बैरल था, लेकिन आज वह बहुत गिर गया और बहुत सेविंग हुई। आपकी उत्पादन लागत पेट्रोल की 23 रुपये है और डीज़ल की 19 रुपये है। आप लोगों ने खुद ही इस सदन में यह जानकारी दी है। फिर आज क्यों 70 रुपये में पेट्रोल बिक रहा है, क्यों 60 रुपये में डीज़ल बिक रहा है? आप नेपाल और बंगलादेश जैसे पड़ोसी देशों में देख लीजिए कि वहाँ यह किस रेट पर मिल रहा है। हम क्यों इतना टैक्स लगा रहे हैं? राज्य सरकारें इतना टैक्स क्यों लगा रही हैं? हम कहते हैं कि आप बता दीजिए। आप यह नोट कर लीजिए कि आप बताएँगे कि क्रूड ऑयल से कितने रुपये में हमारा पेट्रोल और डीज़ल बन रहा है। आप कैरोसीन ऑयल की सब्सिडी घटा रहे हैं, कैरोसीन ऑयल का राज्यों का कोटा घटा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम धीरे-धीरे कैरोसीन-फ्री कंट्री कर देंगे, लेकिन अभी गाँवों में सबको बिजली उपलब्ध नहीं है। हमारी यह बहन ज्यादा जानती होंगी कि जब यह सरकार बनी थी, तब गैस सिलेंडर लगभग 500 रुपये का था, जो आज 800 रुपये का हो गया है, लेकिन उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है! "उज्ज्वला योजना" के नाम पर लोग यह भूल गए कि आज सिलेंडर की कॉस्ट कितनी हो गई है। आपने 500 रुपये के सिलेंडर को 800 रुपये का कर दिया।

श्री गिरिराज सिंह : देखिए, अभी आप ऋषि-वाणी बोल रहे थे, फिर आप गड़बड़ा रहे हैं। आप ऋषि-वाणी बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : हम कतई नहीं गड़बड़ा रहे हैं। हम सत्य बोल रहे हैं, हम असत्य से दूर हैं। आज सिलेंडर की कीमत इतनी बढ़ गई, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। आखिर सरकार क्यों नहीं बताती कि हमने सिलेंडर की कीमत को इतना क्यों बढ़ा दिया? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम इतने हाई क्यों हैं? अगर आप इस देश में पेट्रोलियम पदार्थ सस्ते कर दें तो महँगाई अपने आप रुक जाएगी। आपको लगता है कि हमारा थोक सूचकांक गिरा, फुटकर सूचकांक गिरा, सरकार घोषणा कर देती है कि महँगाई घटी। महँगाई कहाँ पर से घटी? आज 100 रुपये का नोट तो कोई जेब में रखना नहीं चाहता और अगर कहीं किसी भिखारी को एक रुपया या दो रुपये दिया जाए, तो शायद वह गाली देगा।

(2आर/एमसीएम पर जारी)

MCM-KR/2R/3-15

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : दस रुपए से नीचे तो भिखारी भी नहीं ले रहा है आज इस देश में। तो हम आज कहां खड़े हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अगर क्रूड ऑयल की कीमत गिरती है, तो पेट्रोल की कीमत के बारे में आपने कहा कि हमने मार्केट पर छोड़ दिया है। पेट्रोलियम कम्पनियां मज़े करने लगीं और कहते हैं कि हम सरकार के अधीन नहीं हैं, हम फ्री हो गए। ऐसा पेट्रोलियम कम्पनियां कह रही हैं।

हमने एक दिन दवा का मामला उठाया था कि जेनेरिक और नॉन-जेनेरिक दो दवाइयां जो आपने बनानी शुरु कीं, बस, मैं खत्म किए दे रहा हूं, क्योंकि और लोग भी बोलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी स्वास्थ्य नीति की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री जी

पिछले दिनों सदन में स्वास्थ्य नीति की घोषणा कर रहे थे। अखबारों में बड़ा मोटा-मोटा विज्ञापन छपा कि यह सरकार जिम्मेदारी लेती है कि हरेक के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार लेगी कि कोई गरीब दवाई से वंचित नहीं होगा, कोई गरीब इलाज से वंचित नहीं होगा। आपने कैसे ले ली जिम्मेदारी? अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, सी0एच0सीज़0, पी0एच0सीज़0 खाली हैं। प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ तो वह इतनी जांचें लिख देगा, जिसमें उसका इतना कमीशन हो जाएगा। ब्रांडेड कम्पनी की दवा और जेनेरिक दवा के दाम में सौ गुना अंतर है। आप जेनेरिक खरीदेंगे तो 10 पैसे की मिलेगी। आज विश्व में कहीं भी डॉक्टर एंटीबॉयटिक दवा लिखते नहीं हैं। यहां खांसी आ जाए, जुकाम आ जाए, छींक आ जाए, आप डॉक्टर के पास चले जाओ तो वह पहले 7 दिन के लिए एंटीबॉयटिक लिख देगा। कोई एंटीबॉयटिक की गोली 70 रुपए से कम नहीं है। कैसे आप दवा मुफ्त दे देंगे? आप हैल्थ पॉलिसी को डिक्येलर करेंगे, जैसे पूरे वर्ल्ड में इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो गरीब जिस अस्पताल में इलाज कराएगा बीमा कम्पनी उसकी जिम्मेदार होंगी पैसे के लेन-देन के लिए। तब तो हम समझें कि पॉलिसी बहुत अच्छी है। .....(समय की घंटी)..... आपका डॉक्टर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है, अस्पतालों पर कोई कंट्रोल नहीं है। एम्स में तीन-तीन साल के लिए मरीजों को तारीखें मिल रही हैं। एम्स में आप किडनी बदलवाने चले जाइए, हार्ट की दवा कराने चले जाइए तो छ: महीने या एक साल से पहले आपको तारीख नहीं मिलेगी। सफदरजंग अस्पताल चले जाइए, जहां भीड़ लगी हुई है। ऐसे ही मैक्स वगैरह चले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल तो बड़े-बड़े लोग जा सकते हैं, गरीब तो उसके अंदर घुस ही नहीं सकता।

वहां दरबान नहीं घुसने देगा। कहां लाठी लेकर गरीब घुसेगा? तो आप कैसे स्वास्थ्य देंगे, आप यह तो बता दीजिए।

श्री उपसभापति : नरेश जी, अब कंक्लूड कीजिए।

श्री नरेश अग्रवाल : अब मैं खत्म किए देता हूं, डिप्टी चेयरमैन साहब का आदेश है। आप जो करिए सही करिए। जैसे पिछली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था कि किसी की किडनी या किसी के हार्ट का इलाज होगा तो उसका बिल राज्य सरकार बियर करेगी। अब केन्द्र सरकार से घोषणा करा दीजिए, यदि कोई भी गरीब इलाज कराएगा तो उसका रिएम्बर्समेंट केन्द्र सरकार देगी। हम समझेंगे कि गरीबों का इलाज हो रहा है।

आप चुनाव-सुधार की बात कर रहे हैं। अभी परसों डिस्कशन के लिए यह आएगा। उत्तर प्रदेश में कितना पैसा खर्च हुआ? सर्वे में आया है कि 5,500 करोड़ रुपया पूरे देश में इस बार चुनाव में खर्च हुआ। आपने कह दिया कि अब कोई नकद दो हजार से ऊपर नहीं लेगा। तो यह रुपया कहां से आया? उत्तर प्रदेश में बी0जे0पी0 के प्रत्याशी को एक-एक करोड़ रुपया दिया गया। इतना रुपया कहां से आया? कहां हुई चुनाव-सुधार की बात, कौन सा हुआ चुनाव-सुधार, वह एक-एक करोड़ रुपया कहां से आया? आखिर चुनाव-सुधार पर तो हम सब राजी हैं। इस पर परसों हम लोग डिस्कशन कर लेंगे।

महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि कम से कम विदेश नीति भी ठीक कर लीजिए। विश्व में हमारे देश के जो नागरिक मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, अमेरिका ने H1B वीज़ा खत्म कर दिया। तमाम हिन्दुस्तानी अमेरिका से वापस आ रहे हैं। कम से कम इन

चीजों को फिर से रिव्यू कर लीजिए। जहां देश का प्रश्न आएगा, हम सब आपके साथ खड़े होंगे। हम राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं, जब देश का प्रश्न आएगा, लेकिन जहां राजनीति का प्रश्न आएगा, हम जरूर अपने विचार देंगे, अपनी बातों को कहेंगे, हम सुधार भी करेंगे, आलोचना भी करेंगे। हमारी आलोचना को व्यक्तिगत मत लीजिएगा, हमारी आलोचना को यह समझ लीजिएगा कि विपक्ष ने हमको आईना दिखाया है, हम किस आईने को देखना चाहते हैं, यह हमारे ऊपर है। मैं समझता हूं कि अगर इन विचारों को लेकर हम सब राजनीति करेंगे, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो इस राष्ट्र के निर्माण में कहीं न कहीं हमारा योगदान होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बजट स्पीच समाप्त करता हूं।

(समाप्त)

(2S/SC पर आगे)

KS/2S/3.20

SHRI R. VAITHILINGAM (TAMIL NADU): Hon. Deputy Chairman, Sir, with the grace and blessings of hon. *Amma*, the late Chief Minister of Tamil Nadu, I stand here in the Upper House of Parliament to make my maiden speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can take a maximum of 20 minutes.

SHRI R. VAITHILINGAM: Thank you, Sir.

Sir, I heartily thank hon. *Amma* for this great gesture in making me a Member of this august House in 2016 and making me stand here before all of

you to make this first-ever speech in this House. On this occasion, I would like to pay my rich tribute to hon. *Amma*.

(THE VICE-CHAIRMAN, DR. SATYANARAYAN JATIYA, in the Chair)

Even though she is not in our midst today, she lives on in everybody's hearts. Moreover, she had been a Member of this House. The able leadership of *Amma* is seen as an appreciation of the many welfare measures that hon. *Amma* has unleashed for the people of Tamil Nadu and her success is being lauded not only by the people of this country but also the entire Tamil population all over the world. They also recognize that hon. *Amma* has scored a hatrick having won the 2011 Assembly Elections, the 2014 General Elections and the 2016 Assembly Elections. As far as I am concerned, before making me an MP in this august House, she had made me an MLA three times, from 2001 to 2016. In those 15 years, she had made me a Minister in the Tamil Nadu Cabinet twice. I pay my respects to her for this.

Sir, coming to the Budget, to begin with, I once again pay my obeisance to hon. *Amma* for having given me this opportunity to stand here and participate in the discussion on the Budget presented by the hon. Finance Minister.

There are many pending issues with the Centre pertaining to Tamil Nadu, especially those regarding funds. They have been presented in the form of a memorandum to the hon. Prime Minister by the Chief Minister of Tamil Nadu on 27th February 2017.

Following the failure of the monsoon, Tamil Nadu is presently reeling under severe drought. A Central Team also visited Tamil Nadu to make an on-the-spot assessment of the drought situation from 21st to 24th January 2017. In this connection, I request the hon. Finance Minister to kindly accord sanction for the immediate release of Rs. 2,500 crores from the National Response Fund to the Government of Tamil Nadu for mitigating the drought situation.

The House may also recall that Tamil Nadu experienced heavy floods in 2015, and also a severe cyclone, *'Vardah'*, in December 2016. This also has caused tremendous damage of life and property in Tamil Nadu. The State Government had assessed the requirement of funds with regard to cyclone *'Vardah'* alone as Rs. 22,573 crores. I request the hon. Finance Minister to kindly allocate sufficient funds immediately.

Coming to GST, as a manufacturing State, Tamil Nadu is going to incur a huge financial loss. As a part of the road-map for implementation of GST, the Central Sales Tax rate was reduced from 4 percent to 3 percent from 1.4.2007, and further brought down to 2 percent from 1.6.2008. The Centre assured that the States would be adequately compensated. So, the Tamil Nadu Government made a claim of Rs. 13,227.46 crores, but there is still a balance of Rs. 5,571.87 crores to be reimbursed by the Centre. I request the hon. Finance Minister to look into this and release the balance amount immediately.

(CONTD. BY RSS/2T)

SHRI R. VAITHILINGAM (CONTD.): Sir, late Chief Minister of Tamil Nadu had continuously urged the Government of India to implement the "Interlinking of the Mahanadhi-Godavari-Krishna-Pennar-Palar-Cauvery-Vaigai rivers" and further, with the Gundar river, and to divert the surplus water of the West-flowing Pamba and Achankovil rivers to Vaippar in Tamil Nadu.

Though the Special Committee, constituted for this purpose, had held 11 meetings so far, nothing concrete seems to have been done. Moreover, hon. *Amma* had urged the Government of India to nationalize all the Inter-State rivers. I request the Government to ponder over this point, and allocate sufficient funds for intra-linking of rivers so that the country is rid of the water problems, for all times to come.

Due to the untiring efforts of our leader, late Chief Minister of Tamil Nadu, the final order of the Cauvery Water Disputes Tribunal was notified by the Government of India in 2013. She had been urging the Centre for the early formation of the Cauvery Management Board and Cauvery Water Regulation Committee for the effective implementation of the final order of the Tribunal. Though the Centre had promised to constitute them, in a sudden turn of events, now it said that it has to come before Parliament. I would like to point out that so far, in no case, it has been done like this. So, it is neither appropriate nor fair to take a different stand now.

The farmers of the delta areas of Tamil Nadu- I am also one of the members belonging to this region- are dependent on the

Cauvery waters for irrigation, and are agitated over long delay in forming them. I request the Finance Minister to constitute them early so that the order of the Tribunal can be effectively implemented, and Tamil Nadu gets its due share of water.

Coming to the fishermen issue, as late as on 6th March, an innocent fisherman from Rameswaram was shot dead by the Sri Lankan Navy, when he along with a group of fishermen, were fishing in the Indian traditional water between Dhanushkodi and Kachchatheevu. The attack and harassment of fishermen by the Sri Lankan Navy is continuing unabated; their fishing gears and other equipments are being taken away, affecting their livelihood. Unconstitutionally, Kachchatheevu had been ceded to Sri Lanka. The two Agreements of 1972 and 1974 are not ratified by the Parliament, and so, they become invalid and unconstitutional. So, the Government of India should take steps to abrogate the Agreements and retrieve Kachchatheevu, so that traditional fishing rights of the Indian fishermen from Tamil Nadu can be restored.

Diversification of fisheries sector and comprehensive special package for this purpose were very dear to our hon. leader, late CM

of Tamil Nadu. Without elaborating further on this, I request the hon. Finance Minister to sanction adequate funds for this purpose, and release them early, so that fisheries sector of Tamil Nadu can be developed, as imagined by the late CM of Tamil Nadu.

(contd. by 2u/KGG)

KGG/3U/3.30

SHRI R. VAITHILINGAM (contd.): As regards National Eligibility-Cum-Entrance Test, NEET, our leader, late Chief Minister hon. Amma had emphasized that introduction of NEET is a direct infringement on the rights of the State and would cause grave injustice to the students of Tamil Nadu, who are already covered by a fair and transparent admission policy, which is working very well. In this regard, Tamil Nadu also passed Tamil Nadu Admission in Professional Educational Institutions Act, 2006, which has been upheld by the Madras High Court and approved by the Supreme Court. That being so, forcing the students of Tamil Nadu to take up NEET would adversely affect the socially and economically backward students. In this regard, the Tamil Nadu Assembly unanimously passed two Bills for protecting the existing admission policy for admissions in Medical and Dental

Colleges. They have been approved by the Governor of Tamil Nadu and were sent to the Central Government for obtaining the assent of the hon. President of India.

Hence, I request the Centre to kindly urge the hon. President of India, to accord sanction for these two Bills, which would go a long way in protecting the interests of the rural students of Tamil Nadu.

In the Union Budget for 2015-16, the Government proposed to establish one AIIMS-like institution in Tamil Nadu. Accordingly, five sites were proposed by the State Government, including one in my place, that is, Sengipatti in Thanjavur District. It is learnt that, luckily, Sengipatti in Thanjavur District has been identified as the best-suited location for setting up this AIIMS by the Central Team.

The hon. Chief Minister of Tamil Nadu, who met hon. Prime Minister, on 27th February, 2017, also insisted on establishing AIIMS in Sengipatti of Thanjavur District. I request the Government to take immediate necessary action.

There is another long-pending demand of the people of Tamil Nadu. That is to make the ancient language of Tamil as the official language of the Government of India. Moreover, we strongly urge the Centre to declare all the languages included in the Eighth Schedule of

the Constitution as Official Languages of the Government of India.

Secondly, there has been a long-standing demand of the people of Tamil Nadu to use the Tamil language in the Madras High Court. I once again, request the Centre to kindly reconsider the proposal for the use of Tamil in the High Court of Madras.

With these words, I request the hon. Finance Minister once again to allocate sufficient funds, as was demanded, immediately to tide over the finances of the State. Thank you.

(Ends)

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (TRIPURA): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you. The Budget, presented by the Finance Minister starts with an assumption of 11.75 per cent growth in GDP for 2017-18, calculated over the revised figures of 2016-17. An analysis of the allocations under the SC/ST Sub-Plan reveals a recurring trend of under-allocation in 2017-18, wherein the SCSP comprises only 2.5 per cent and the TSP only 1.53 per cent of total allocations, which is not even the half of the mandated amount.

(Contd. by KLS/2W)

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (CONTD): Food, including the allocations under the National Food Security Act, kerosene and LPG

subsidies have a direct impact on women. The share of these in the Budget has come down from 9.5 per cent in 2015-16 to 7.9 per cent in 2017-18. Moreover, there is no gender budget component in any of these except the LPG subsidy which is Rs. 3,200 crore. The Finance Minister also stated that the allied sector of dairy development and fisheries, which provides livelihood to a lot of women, would receive a major boost through an increased allocation of Rs. 8,000 crore. However, there is no women specific allocation in either dairy or fisheries. The only agricultural scheme that has allocations for women in the agricultural sector is the National Food Security Mission where a nominal increase of Rs.60 crore has been made in the gender budget, which actually accounts for less than 30 per cent of the entire allocation. Sir, ICDS Budget 2017-18, like the previous budgets, has criminally neglected India's eight crore malnourished children under six and two crore pregnant women and lactating mothers by not increasing the allocations for the Integrated Child Development Scheme. The Budget Estimates for the ICDS for 2017-18 is only Rs.15,245.19 crore. It is even less than the budget allocation for ICDS in 2015-16, which was Rs.15,433.09 crore and Rs. 18,108 crore in 2014-15. It is only half of the 12th Plan allocation for ICDS for the year 2017-18 which is Rs. 30,025 crore. The Budget boasts about the much promoted Prime Minister's announcement of the maternity

benefit of Rs.6,000 to pregnant women. This is nothing new and it has been included in the Right to Food Act. But ironically the amount earmarked for the Maternity Benefit Programme is a mere Rs. 2,700 crore which will cover only 17 per cent of the 2.6 crore live child births per year in India. These maternity benefits come as a cash transfer scheme on the condition of institutional deliveries. Sir, a dangerous move made in the Budget is the announcement by the Finance Minister to set up 'Mahila Shakti Kendra' in the Anganwadi Centres. This is nothing but putting the Anganwadi Centres at the disposal of the corporates. In the present situation half of the Anganwadi Centres are not even having basic facilities such as drinking water or their own buildings. Though there are no proposals for direct cash transfer in place of schemes like ICDS, the Economic Survey sets the direction for direct cash transfer in the name of the Universal Basic Income Scheme. The increased allocation of Rs.2700 crore for maternity benefits comes as a cash transfer scheme on the condition of institutional deliveries.

(Contd by 2X/SSS)

SSS-LT/2X/3.40

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (CONTD.): The Government has completely failed to respond on the issue of rising violence against women

and the need to ensure budgetary support for survivors of violent crimes. This can be seen in the atrocious cut in the allocation of resources for the Nirbhaya fund. The revised estimate for the Nirbhaya fund in 2016-17 was Rs 585 crores and this has been now cut to Rs. 400 crores. The total schemes for Scheduled Castes has been reduced from Rs. 294 crores to Rs. 256 crores only and the total schemes for Scheduled Tribes is brought down to only Rs. 261 crores from Rs. 307 crores in 2016-17. Only eleven new schemes for SCs and eight new schemes for STs have been introduced in 2017-18. Sir, in the Union Budget of 2017-18, the total allocation for the development of the North-East region has been increased from Rs 32,180.08 crores to Rs 43,244.64 crores, which is exclusive of TSP and SCSP allocations. In addition to this, a total of Rs 716 crore from the TSP and Rs 53 crore from the SCSP has also been allocated for the Ministry of Development for North Eastern Region. But still, other than one single scheme for skill development, there has been no other new scheme introduced for the development of the North-Eastern Region. It shows that there have been major budgetary cuts for the programme related to food and public distribution, electronics and information technology, environment, forest and climate change and urban development. (Time-bell). One minute, Sir. Sir, the surrender of goals like the alleviation of

poverty, focusing on the special needs of women, *Dalits*, tribals and other deprived sections of society, through the allocation of budgetary resources for them, in favour of tax cuts for the corporate and the elite classes, exposes the real anti-people agenda of the Government. Sir, to sum up, this Budget not only ignores, but also imposes further burden on the people in the wake of demonetisation and widespread deflationary conditions. This Budget clearly upholds the interests of the market. It has no place for women. It is once again a blatant attack on the poor and the oppressed. This is a budget to appease the rich accentuating the problems of unemployment and rising inequality. Thank you.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Shri C. M. Ramesh. Not present. Shri K. T. S. Tulsi. Not present. Shri Swapan Dasgupta. Not present. Shri Abdul Wahab. Not present. Shri Tiruchi Siva.

(Followed by NBR/2Y)

-SSS/NBR-KLG/2Y/3.45.

SHRI TIRUCHI SIVA (TAMIL NADU): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir.

Sir, 'Incredible India", sometimes, becomes 'indelible India.' Demonetisation, which was proudly announced by the hon. Prime Minister, has not achieved its intended purpose, but its unintended consequences have devastated the lives of poor and crippled our economy.

Sir, in 2004, Dr. Manmohan Singh, demonetized some higher denomination currency. But, it gave no pains to the people. Now, the days seem to be over, but the scar is still there. Our people are used to live with miseries. The demonetization was done with some purpose -- to curb black-money, to stop corruption as well as to unearth black-money. But, what happened, actually, was not that. The suffered were only the common man.

There is nothing mentioned even in the Budget speech. The hon. Finance Minister boasted so much and is proud of demonetization. But, Sir, there is no mention about the ways, methods or means to unearth black money from other sources i.e., by way of benami real estate investments, off-shore accounts and gold and precious metals. It is said, very clearly -- even the hon. Finance Minister has accepted it on the floor of the House during the Question Hour -- that out of total black money, only 6 per cent is in the form of cash and this 6 per cent is not with the common man. But, the person who underwent all miseries is only the common and poor.

Sir, shadow economy is prevalent in all developing economics; no country is an exception to it. For example, in the USA, 8.6 per cent of its GDP is shadow money. In China, it is 12.7 per cent. In Japan, it is 11 per cent and in India, it is 22.2 per cent. The ratio may be different; but, it is quite common and prevalent everywhere. But, no country has taken the severest step. My simple doubt is: If you say that it curtails black money and stop counterfeit currency, it is a myth. Yesterday there was a news item that the entire Chennai port was cordoned off because there was information that about Rs. 400 crores have come as counterfeit from Pakistan and they are all in Rs. 2000 denomination! How is it possible? So, when one person can print something, another person can imitate it sometime or later. Our basic doubt or query or apprehension is, when you feel black money could be stored in Rs. 500 or Rs. 1000 denomination, it would be easier with Rs. 2,000 notes. What they had stored earlier in Rs. 500 or Rs. 1,000 notes can now store double the money with Rs. 2,000 notes. But, if one says that the flow of money is not so easy is not correct. During demonetization period, people were not able to solemnize marriages in their own families. Many families could not perform marriages. It is because, Sir, only Rs. 2 lakhs was permitted to be spent on a marriage. And, looking at our culture and tradition, no marriage can be performed with

Rs. 2 lakhs. So, people suffered a lot. But, at the same time, there were some marriages which celebrated pompously. And it was told that money spent was accounted. But, the point is, how they got it? When there was restriction with regard to withdrawal, when no one can withdraw more than a fixed amount in a week, how crores of rupees were spent in white money? It is a very big question. So, we expected that, at least, the hon. Finance Minister, in his Budget, would come out with a fact as to how much black money has been unearthed through demonetization. Sir, 85 per cent of currency is of higher denomination. When higher denomination was demonetized in 1978, it was around 1-2 per cent. Sir, Rs. 1,000 note was unreachable for the common man. But, today, 85 per cent of currency is in the form of Rs. 500 and Rs. 1,000 notes. Even a coolie or labourer or farm worker has got Rs. 500 and Rs. 1,000 note. And you say that black money is with him! For example, a tea stall owner who opens his shop early in the morning and closes it at night saves some money every day. He preserves that money for his daughter's marriage. He cannot go to a bank and deposit it. He keeps that money in his box or keeps it at his house. Over the years, it gets multiplied up to Rs. 2 lakhs or Rs. 3 lakhs or Rs. 5 lakhs. Then, he is ready for marriage. And, all of a sudden you demonetize money and when he carries that money to bank, they ask, 'what is the source?'

PK-AKG/2Z/3.50

SHRI TIRUCHI SIVA (CONTD.): 'Every person can deposit only up to Rs.2.5 lakh', that is what they said, and even that will be probed into. This person saved five rupees, ten rupees, or, hundred rupees everyday and it got multiplied over years together. He saved it like anything. He did not sleep at all. He kept it under his head. He was keeping it at home. All of a sudden, demonetisation came. When he took it to the bank, it was considered as black money. But, actually, the black money holders are very safe. They had already shifted their money to the safest place. Everyone knows that. That is what I said. What are the methods and means you have in hand to unearth the black money which is in offshore accounts, which is in the form of real estates, which is in the form of gold and precious metals, mining and everything. It is a very simple thing. For example, if you go to a town or a place, find a house unoccupied, not renovated and it has been lying there for quite a long time in a posh area, it is black money. If you find hundreds of acres on a highway unutilised, or, nothing has been constructed on it, it is black money. What is the proposal the Government is having to deal with all these things? We have seen how people were waiting for their money! There were long queues outside the

ATMs; no one cared about that. So many people, more than 100, died. The people who get pension every month, who have been deserted by their children and who live their life by way of that pension, were getting the pension but they were not able to withdraw that money. They were forced to stand in the long queues. They fainted, they starved out of hunger and some people even died. No one cared about them. My basic doubt is this, Sir. When you switch over to a new currency, of a higher denomination, shouldn't you apply your mind that the currency should fit into the already existing ATM machines? The existing ATMs were not in a position to operate with the new currency because the size was different. So, everything was amiss. Sir, the intention may be good, but the implementation process was very, very bad. Now, the people have become used to that. That is what I said in the beginning itself. If the bus fare is hiked, the people will be shouting at it, but they will be paying for it. If the petrol price is hiked, they will be feeling for it, but they will be paying for it. Like that, for the past three months, they have been accustomed to demonetisation and they are now used to new 2,000 rupee notes. You know what the value of Rs. 100 in those days was. We were not able to shell out to anyone. My another very basic doubt is this. An ordinary vendor on a roadside does selling of at least Rs.2,000 - Rs.3,000 per day.

Suppose his transaction is of Rs.3,000/-. His profit will be Rs.500/-. He eats with that and he spends with that. But, now, when you bring in the cashless society, just imagine if that comes into operation, these Rs.3,000/- will be transacted by way of card or something like that. It will be accounted. Per month, what will be his income? It will come to about Rs.1,00,000, and per year, it will be Rs.12,00,000/-. What will be his tax slab? It will be the uppermost slab. So, a person who earns only Rs.500/- per day, and living on it, his income will be shown as Rs.3,000/- per day, as a result, his income per month will be Rs.1,00,000/-; for a year, it will be Rs.12,00,000/-, and he will come under the uppermost slab. He will be required to pay 30 per cent tax, means he will have to pay Rs.4,00,000/- as income tax and he would have nothing at all with him. What he earned, he has already spent. These are all very basic things which anybody should have speculated. You are worried about black money as every one other is, but what is the way out of it. That is what we are again and again asking. I ask it in another way. As I said, when Rs.500/- and Rs.1,000/- could increase black money, why not Rs.2,000/-? For example, the US, which is considered to be the richest country in the world, its highest denomination is only 100 dollars. The Britain whose finances or wealth are equivalent to half of the world, they say, the highest denomination is 50 pounds. In other

European countries, it is 50 Euros. So, they have 100 Dollars, 50 Pounds and 50 Euros whereas you are shifting from Rs.500, or Rs.1,000 to Rs.2,000/-. I think these are not the ways and means.

(Contd. by PB/3A)

PB/3A/3.55

SHRI TIRUCHI SIVA (CONTD.): So, the country has gone through a very bad thing and, therefore, at least, in the Budget Speech, we expected the Finance Minister to say how much money has been unearthed. But nothing has come out. If at all so much money was in floating, people were using it, how much was deposited? All that money that has not been deposited, that is black money. So, those people who were not able to deposit it would have done it in some other manner. How much money has been deposited, how much was in use, how much money is black money, no, Sir, no such information from the Finance Minister was given even in his Budget Speech. Everyone has spoken about demonetization and I have to also say something about it because everyone suffered. Even we went to the Bank in the Parliament House. They said, you will be getting only four thousand rupees and that four thousand rupees was for one week. The next week, I had to go there again to get four thousand rupees. It is highly ridiculous. We

cannot just live on four thousand rupees a week, and they expected the people of this country to get along. They said, 'It is a short-term pain and long-term gain.' No, Sir. There is no short-term pain. It is a long-term pain and not even short-term gain. The Government can be proud of it. Of course, your measures are good, your intention is good, but the implementation part spoiled everything else. So, in that way, the country has gone through a very, very bad period and the people went through very miserable days and now they are getting out of it. I am afraid, again, even the last man would be suffering in the coming days; and everyone will be accountable.

Sir, the Internet connectivity is only 16.1 per cent in this country. Only 47 per cent of the people are having bank accounts but you want them to enter into cashless society. They don't know what is Internet. They don't know how to operate a mobile phone like that. So many people are still left out with it. I may have two phones, another one may have three but many people do not have mobile phones. They do not ABC, they do not know alphabets, they do not know numbers, but you expect them to transact cash by way of cashless society! Sir, we are living in India. We have to legislate laws and we have to bring out schemes suited to our people, not to Netherlands, not to other countries which have succeeded. We cannot

compare them. There are some countries where there are hundred per cent taxpayers. But, here, in our country, it is not so. People are uneducated. People are not updated with Internet literacy. They do not know what is mobile, what is bank account and all that, but you expect them to come into cashless society! Sir, it is too hasty a decision. It has to go step-by-step. All of a sudden, one fine night, it was declared that these currencies would not be valuable and it was demonetized and the whole country went into very bad days. My only observation is that even after that if you have achieved by way of getting some black money through this, you should have told that in the Budget which is not there.

Sir, along with that, I have two-three very, very important points. Another is about public sector undertakings. The Government is very keen in disinvesting the public sector. Sir, Pandit Jawaharlal Nehru while inaugurating the Bhakra Nangal Dam had said, 'The Public Sector Undertakings are the temples of our economy.' Sir, it is not only an organization which generates employment, it also helps our economy. You know very well, Sir. We have been in various Committees and we have also been studying the functioning of the Public Sector Undertakings. If the private sector is earning something, it is the wealth of one person but if the public sector is earning something, it is the wealth of the country. If, at all,

the public sectors are failing somewhere, we have to go into its reasons and plug the loopholes, whereas, we are trying to wind it up. For example, take the Salem Steel Plant in Tamil Nadu which had been installed there after a lot of pains and strains in those days when the DMK was in power and Mrs. Gandhi was in power. But now it is about to the disinvested or closed. Sir, it has been spread out in four thousand acres of land and it has got so much of worthy minerals. If you are selling it out, any private person will take it off. The Government money will go to the private person. That money will also be spent by the Government for various schemes. So, I urge, Sir, just kindly look into the restructuring and revival of Public Sector Units, and resilience of the Public Sector Units alone will save the economy of the country. Kindly don't go into disinvestment.

(Contd. by 3b/SKC)